आधार पर दीखता है कि बढा है। जब हम पूछते हैं क्यों बढा, तो कहते है डिवेल्यूएशन हुआ। तब तो डिवेल्यूएशन के हिसाब से बढना चाहिये -1.57 के हिसाब से। यह बढा है उस से ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में क्या यह कारण बतायेंगे कि यह क्यों बढा ? अब आप दूसरा आधार लेंगे कि हम एलोकेशन कम करते जा रहे है, तो जब हम कम करने का प्रयत्न करते जा रहे हैं, तो जनवरी तक ही 80 कैसे हो गया, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये, फालतू का जवाब नहीं चाहिये।

श्री दिनेश सिंह : कैसे बताऊं इसका स्पष्टीकरण। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि जितना वह मांगते थे, उससे कम परसेन्टेजवाइज हम करते जा रहे है . . .

श्री राजनारायण : कितना मांगा रहे हैं ? श्रीमन् क्या मंत्री जी बताएंगे कि मेक्सिमम सीलिंग क्या है ?

श्री दिनेश सिंह अगर हर साल आकडे की सिलिंग माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं वह सदन के सामने रख दूंगा।

MR. CHAIRMAN: I am sorry I have given more than 22 minutes for this question. Next question.

मिलों द्वारा तैयार किये गये कपड़े के मूल्य में बढोत्तरी

*209. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** :†
श्री के० सुन्दरम् :
श्री सुरजीत सिंह अटवाल :
सरदार रामसिंह :
श्री निरंजन वर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अक्तूबर, 1964 से अप्रेल, 1967 के बीच मिलों द्वारा तैयार किये गये कपड़े के दामों में कब-कब कितनी-कितनी बढ़ोत्तरी की अनुमति दी गई है ;

(ख) इसी काल-खंड में कपड़े के उत्पादन व्यय में कितनी बढोत्तरी हुई; और

(ग) उपभोक्ता को निर्धारित मूल्य पर कपडा उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ?

‡[INCREASE IN PRICE OF MILL-MADE CLOTH

*209. SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI:†
SHRI K. SUNDARAM:
SHRI SURJIT SINGH ATWAL:
SARDAR RAM SINGH:
SHRI NIRANJAN VARMA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the extent to which increase has been allowed in the price of mill-made cloth from October, 1964 to April, 1967 together with dates on which such an increase was given effect to;

(b) the increase in the cost of production of the cloth during the said period; and

(c) the steps that are being taken by Government to make available the cloth to consumers at fixed price?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल रखा जाता है।

विवरण

अक्तूबर 1964 से मिल के बने कपडे की नियन्त्रित किस्मों (अर्थात धोती, साडी लटठे तथा ड्रिल) के कारखाने से निकलते समय के मूल्यों मे ऐसे कपड़े के उत्पादन की

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sundar Singh Bhandari.

‡[ ] English translation.

लागत में हुई वृद्धियों के फलस्वरूप निम्न अवसरों पर संशोधन किया गया :—

संशोधन की तारीख	कपड़े के विभिन्न वर्गों में कारखाने से निकलते समय के मूल्यों में हुई वृद्धि
1 मार्च 1965	1.8 प्रतिशत से 3.3 प्रतिशत
1 नवम्बर, 1965	1 38 प्रतिशत से 5 प्रतिशत
1 अप्रेल, 1966	मोटे तथा मध्यम श्रेणियों के सम्बन्ध में लगभग 2 प्रतिशत और बढ़िया तथा बहुत बढ़िया श्रेणियों में 7 से 11 प्रतिशत।
1 अक्तूबर, 1966	6 प्रतिशत
15 अप्रेल, 1967	4.5 प्रतिशत

कपड़े की अन्य किस्मों के मूल्य नियंत्रित नहीं किये जाते।

कपड़े के उत्पादन की लागत में वृद्धि अधिकांशतः रुई के मूल्य में वृद्धि तथा साथ ही मिल भंडारों की लागत में वृद्धि, मिलों के अनिवार्य बंद होने के कारण ऊपरी खर्चों में वृद्धि के अतिरिक्त सांविधिक मजदूरी स्तरों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप हुई। यद्यपि उद्योग ने साधारणतया मूल्यों में कुछ अधिक वृद्धि के लिये मांग की थी, परन्तु वास्तविक वृद्धियों का निर्धारण न केवल ऐसे कपड़े के उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रख कर किया जाता है अपितु वर्तमान परिस्थितियों में यथासम्भव कम मूल्य पर उपभोक्ता को नियंत्रित कपड़ा देना सुनिश्चित करने की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जाता है।

समस्त देश में नियंत्रित कपड़े की उपलब्धि पर निरन्तर सावधानी रखी जा रही है।

†[THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) to (c) A statement is placed on the Table of the House.

†[ ] English translation.

STATEMENT

Since October, 1964, the ex-mill prices of controlled varieties of mill-made cloth (*viz.* dhoty, saree, long-cloth, shirting and drill) have been revised on the following occasions taking into account the increases in the cost of production of such cloth:

Date of revision	Extent of increase in ex-mill prices in the different cloth groups
1st March, 1965 .	1·8 percent to 3·3 percent.
1st November, 1965 .	1·38 percent to 5 percent
1st April, 1966 .	About 2 percent in respect of coarse and medium categories and 7 to 11 percent in fine and superfine categories
1st October, 1966 .	6 percent
15th April, 1967 .	4·5 percent.

The prices of other varieties of cloth are not controlled.

The increase in the cost of production of cloth was largely due to the increases in the price of cotton as also increases in the statutory wage levels apart from increases in the cost of mill stores, increased overheads due to compulsory closure of mills. While industry's claim for increase in prices has usually been somewhat higher, the actual increase is determined after taking into account not only the increases in the cost of production of such cloth but also the paramount need under the existing circumstances, of ensuring supplies of controlled cloth to the consumer at the lowest possible price.

A constant watch is kept over the availability of controlled cloth through out the country.]

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : जो वक्तव्य आपने रखा है उसमें मूल्य वृद्धि के लिये रुई के मूल्यों में वृद्धि की बात का समावेश किया । मैं मंत्री जी से यह जानना

चाहूंगा कि क्या यह बात सच है कि पिछली 12 अप्रैल को जब आपने वक्तव्य प्रसारित किया था कपड़ों के मूल्यों के सबध में, तब आपने यह केटेगारिकली कहा था कि रूई के मूल्यों में वृद्धि की सभावना नहीं है और अगर यह बात सच है तो अब मूल्यों की वृद्धि मे रूई के मूल्य की वृद्धि का किस आधार पर इसमें समावेश करते समय आप जस्टिफिकेशन देते है---यह मेरा पहला सवाल है।

दूसरा यह कि मैने यह भी चाहा था कि जितनी वृद्धि आपने मजूर की है उसी के साथ साथ लागत में कितनी वृद्धि हुई उसके भी तुलनात्मक आंकड़े दिये जायें ताकि यह समझ में आ सके कि आपने जितनी वृद्धि स्वीकार की है उसमें वास्तव मे लागत मे कितनी वृद्धि हुई है जिसके कारण मूल्यो मे वृद्धि करनी पड़ी। यह दूसरी बात मैं चाहूंगा कि कि लागत की वृद्धि के आकड़े भी दिये जांये।

मेरा सवाल (ग) भाग से लगता हुआ यह है कि उपभोक्ता को निर्धारित मूल्य पर कपड़ा उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या क्या पग उठा रही है? यह जो जवाब दिया गया है इसमें उन पगो के बारे---जो स्टेप सरकार ले रही है---उल्लेख नही है। यह इसलिये आवश्यक है कि आज भी सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किये है कई स्थानो पर उपभोक्ताओ को उस मूल्य पर कपड़ा प्राप्त नही हो सकता है क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली है? अगर हा, तो वह कपड़ा उन्हे निर्धारित मूल्य पर प्राप्त हो सके इसके लिये सरकार कौन से कदम उठा रही है। इस उत्तर मे उसका समावेश नही है।

श्री दिनेश सिंह : जहा तक कि रूई के मूल्यों का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैने पिछली मर्तबा सदन में कहा था कि रूई के मूल्य हम अभी नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन रूई के मूल्य तो अक्टूबर 1966 में 5 फी सदी से बढ़े थे और उसका असर कपड़े की बुनाई पर आया। उस समय, अक्टूबर 1966 मे यह कहा गया था---मिल मालिकों से कहा था---कि हम अभी अच्छे कपडे के दाम बढा रहे है, उसमे जो मल्टिप्लायर्स आते है उसके हिसाब से हम बढा रहे है हर छ महीने मे। यह मामला देखा जाता है अप्रैल के महीने मे। तो फिर वह हमारे सामने आया 5 फी सदी जो रुई के दाम बढे थे उसके पहले कोई भुगतान नही हुआ था। तो वह हमारे सामने आया।

इसके अलावा, इस बीच मे कुछ जो मजदूरों का डी० ए० वगैरह बढा था स्टेटयटरिली, उसका भी सवाल था। उद्योग ने हमारे सामने रखा था कि करीब साढे 7 से 9 फीसदी तक वे चाहते थे कि कपडे का मूल्य बढाये। इसमे से उन्होंने ढाई फी सदी तो जो कि रुई की कीमत बढी थी उसको रखा था, और 4 फीसदी उन्होंने वह रखा जो मजदूरो के डियरनेस अलाउन्स वगैरह से बढ़ा था और ले आउट मे उन्होंने 3 फी सदी की बढोतरी की माग की थी। सब को सोच कर हम इस निर्णय पर आए कि साढ़े 4 फीसदी बढ़ाने से इस समय जो खास जरूरियात है उद्योग की, वे भी पूरी हो जायेगी और कम से कम दाम जो हम बढाना चाहते है वह भी उस से पूरा होगा। इस सब को सोचकर साढे 4 फीसदी कपडे की कीमत को गवर्नमेंट ने बढाया।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी मेरे तीसरे (सी) पार्ट का सवाल था.

"the steps that are being taken by the Government".

श्री दिनेश सिंह : जी हा, तीसरा सवाल यह है कि दाम तो केन्द्रीय सरकार मुकर्रर करती है और कपडे पर उसकी छाप लगा दी जाती है, उसके बाद वह कपड़ा आम दुकानो में, बाजारो मे, बिकता है। वह सही दाम पर बिके इसलिए राज्य सरकारो से हमने कहा है कि उनका जो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेन्ट है वह उसको देख करके उस पर नियत्रण रखे। अगर उनको कोई कठिनाई होती है तो उसको हमारे सामने लाते है और हम दूर करने की कोशिश करते है।

अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि किसी खास जगह पर कपड़े की कठिनाई हो रही है तो हम वहां की राज्य सरकार को फौरन लिखेंगे कि वे वहां पर देखें क्या कठिनाई है और जो हो सकता है हम करेंगे।

MR CHAIRMAN: I want to finish those who have put the question and are here.

SARDAR RAM SINGH: May I know, Sir, whether the Government are aware that coarse and medium cloth is selling at much lower prices than the controlled prices? If so, why was it necessary to increase the price recently?

SHRI DINESH SINGH: Here are two statements by two hon. Members. One says that he is having difficulty in getting coarse cloth and the other hon. Member says that it is selling at prices lower than the controlled prices. I wish it sells at lower prices.

SARDAR RAM SINGH: I want to know whether you are aware of it.

SHRI DINESH SINGH: We are not aware.

श्री निरंजन वर्मा : मंत्री महोदय की तरफ से अभी जो स्टेटमेंट सभा पटल पर रखा है उसमें उन्होंने यह बताया है कि धोती, साड़ी लट्ठा तथा ड्रिल में नये किस्म के कपड़े है और इन पर मूल्य की वृद्धि अपेक्षाकृत कम हुई है और जो वृद्धि हुई है वह 2 प्रतिशत और बढ़ी है और बढिया श्रेणियों मे 7 से 11 प्रति शत तक हुई है। तो क्या यह संभव नही है कि यह जो ड्रिल, धोती और साड़ी अधिकांश जनता पहिनती है, साधारण किस्म की जनता पहिनती है, उनके मूल्यों के ऊपर कोई प्रकार की वृद्धि न हो और अच्छे किस्म के जो कपडे है उनके ऊपर अधिक वृद्धि कर दी जाय ताकि गरीब आदमियों के ऊपर उस वृद्धि के परिणामस्वरूप भार नही पड़ सके?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि उन्होंने आगे इसी स्टेटमेन्ट मे बताया है कि मिल भंडारो की लागत मे वद्धि हुई, तो इस से उनका अभिप्राय क्या है? मिल भडारो की लागत मे वृद्धि हुई है जिस के कारण कपडे की मिलो मे प्रभाव पडा।

तीसरी बात यह है कि कन्ज्यूमर्स विजिलेन्स कमेटी एक बनी थी टेक्सटाइल्स के लिये और समय समय पर यह घोषणा की जा रही थी कि मूल्यों की वृद्धि की ओर वह निगरानी करेगी। तो यह जानना चाहता हूं कि आज तक क्या उस कमेटी की कोई बैठक हुई या नही और यदि बैठक हुई तो उन्होंने श्रीमान को क्या सुझाव दिये जिसके कारण मूल्यों की वृद्धि को रोका जा सके?

श्री दिनेश सिंह : सभापति महोदय, पहले सवाल का जवाब यह है कि जो बढिया किस्म के कपडे है उन्ही के दाम बढ़े हैं और जो कन्ट्रोल्ड हैं उन के कम बढे है। यह भी हमारे सामने हमेशा सवाल रहता है, जब हम घटाने की या बढ़ाने की बात सोचते है, क्योंकि हर एक चीज के दाम की भी एक हद होती है, उस से ज्यादा दाम बढ़ जाने से वह फिर बिकती नही है। यह व्यापार में एक मामूली बात है। अब यह नही हो सकता है कि दाम बिलकुल बढ़ते ही चले जाय, यानी जो कन्ज्यूमर है, जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, उनकी भी किसी चीज को खरीदने की एक हद होती है, उस से ज्यादा वे भी नही दे सकते हैं। इसलिये हमने यह दो हिस्से मे रखा था। एक तो जो आम कपड़ा होता है, साधारण जनता के पहिनने की जरूरत के जो कपडे होते है, उनके दाम पर नियत्रण हो और दूसरे के दाम पर नियत्रण न हो, जिस से कि अगर एक मे कुछ नुकसान भी होता है तो दूसरी तरफ से उसको पूरा किया जाय। जहा तक माननीय सदस्य ने दूसरा सवाल पूछा कि जो उद्योग में लागत बढ गई है और और उसकी तरफ भी ख्याल करे।

श्री निरंजन वर्मा : आपने विवरण मे यह दिया है कि "भंडारों की लागत मे वृद्धि हुई है" तो इसका क्या मतलब है?

श्री दिनेश सिंह : लागत में जो वृद्धि हुई, उसका मतलब यह है कि जो कपड़ा बनता था और उसके बनने में जो जो चीज़ इस्तेमाल होती थी, उसको पूरा जोड़कर लागत निकाला जाता है ।

श्री निरंजन वर्मा : आप कृपया विवरण को पढ़िये जिसमें लिखा है" कपड़े के उत्पादन की लागत में वृद्धि अधिकांशतः रुई के मूल्य में वृद्धि तथा साथ ही मिल भंडारों की लागत में वृद्धि" । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि "मिल भंडारों की लागत में वृद्धि" से क्या मतलब हुआ ।

(Interruptions)

श्री दिनेश सिंह . क्षमा करें, मैं इसका मतलब बतलाता हूं । सभापति महोदय, चूंकि रुई की कमी थी, इसलिए हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए मिलों को बंद करने की बात की थी और इसीलिए . . .

SHRI ARJUN ARORA: Sir, neither the Minister nor the hon. Member knows what stores in the textile industry are or what is meant by "stores." "Stores" are not "bhandar" . . . *(interruption)*

There are some people in the House who know something about the textile industry. They will verify . . .

(Interruption)

MR. CHAIRMAN: Let us leave it to the questioner and the questioned.

श्री दिनेश सिंह : मैं पूरी तरह मानता हूं कि माननीय सदस्य श्री अर्जुन अरोड़ा मुझ से ज्यादा व्यापार के बारे में जानते है । लेकिन बात यह थी कि जैसा माननीय सदस्य सवाल पूछ रहे थे वैसा ही मैं जवाब दे रहा था और हम दोनों खुश थे । बीच में अर्जुन अरोड़ा जी ने बात डाल दी जिस की कोई खास जरूरत नहीं थी ।

तीसरा सवाल जो आपने विजिलेंस कमेटी के बारे में पूछा था । इस कमेटी की बीच बीच में बैठक होती रहती है । उनके सुझाव आये और उस पर ख्याल किया गया है । जहां तक कपड़े की कमी और सही दाम पर कपड़ा नहीं मिलना इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई ।

जहां तक दाम बढ़ाने का सवाल है, इस संबंध में एक मल्टीप्लायर्स बना है । एक तरीका हम लोगों ने बना लिया है कि जिसकी वजह से लागत बढ़ती है वह सवाल सामने आ जाता है और उसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती है ।

SHRI A. G. KULKARNI: Will the Government please say whether the Indian Cotton Mills Federation has stated that 40 per cent of their products are under the controlled variety? As against that, is the Government aware that 95 per cent of the cotton grown by the growers is under statutory control for a very long period? Thridly, is the Government aware that they have shown favouritism to the cotton mill industry by ignoring the claims of the cotton grower by increasing its prices and thereby putting him to a discouragement to grow more cotton? And finally, is the Government going to enquire into the calculations submitted by the Indian Cotton Mills Federation as regards increase in prices?

SHRI DINESH SINGH: Sir, the answer to the first two parts is "Yes." The answer to the third is "No". The answer to the fourth is "We shall look into it."

SHRI BALACHANDRA MENON: In view of the Government's promise to set up fair-price shops in all factories having 300 workers or more, will the Government be pleased to allow sale of cloth of cheaper variety at controlled rates or ex-mill rates and what steps will Government take in this regard?

SHRI DINESH SINGH: As I said, controlled cloth is fairly easily available. There is no need at this stage to set up any fair price shop.

SHRI NIREN GHOSH: I would like to know whether forward trading in cotton is contributing to the rise in the raw cotton price and if so, whether Government would consider banning forward trading in cotton. Will the hon. Minister also say whether the per capita availability of cloth has declined? The Government gave an assurance that one day closure in a month will continue only for two or three months. But now that period has expired and more closures have already taken place. I would like to know whether Government would consider running the mills at full capacity without any closure so that more cloth can be immediately made available to the country?

SHRI DINESH SINGH: Sir, so far as forward trading is concerned, there is a Commission on this. So far as cotton is concerned, it is more a question of fixed date delivery rather than forward trading. There is no speculative forward trading in cotton.

SHRI C. P. PANDE: Has it come to the notice of the Minister that the difference between ex-factory price, wholesale price and retail price is rather big and if an attempt is made to bridge the gap between ex-factory price, wholesale price and the retail price, it will be of great benefit to the consumer? In these days of scarcity, if this wide difference between the three prices is reduced, it will be of advantage to the consumer. Has it come to his notice?

SHRI DINESH SINGH: My recollection is that the difference between the mill price and the retail price is 20 per cent. I do not know whether the hon. Member feels it is very high because there is, I am afraid, a high element of distribution charges in this and so this has been fixed at 20 per cent. If the hon. Member feels it is too high, I shall gladly look into it.

MR. CHAIRMAN: We have done one question to-day and we are in the second question now. It is your pleasure that we will do only two questions to-day, I would like to ask. It has become impossible for me, I see the anxiety of Members to put questions, but I think you should leave the discretion entirely to me as to when to stop a question and when to begin a new question.

श्री राजनारायण: श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल यह है और वे कृपया ध्यान देकर सुनें। वास्तव में सेक्रेटरी उत्तर बनाकर दे देते हैं और मंत्रियों को अपने कार्यालय में उसको पढ़ने की फुरसत नहीं होती है क्योंकि वे इस तिगड़म में लगे रहते हैं कि आगे कौन प्रधान मंत्री बनेगा। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि कानपुर के बाजार में कोर्स और मीडियम कपड़े का जो कंट्रोल रेट है, उससे बहुत ही कम कीमत पर वहां पर बिक रहा है।

श्री अर्जुन अरोड़ा: फाइन और सुपरफाईन महंगा बिक रहा है।

श्री राजनारायण: वह तो हम खरीदेंगे नहीं, सुपरफाइन तो मंत्री खरीदेंगे।

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let there be no cross questions.

श्री राजनारायण: मेरा सवाल यह है कि जब कंट्रोल रेट से भी कम कीमत पर सामान्य जनता के लिए कपड़ा बिक रहा है, इस बारे में सरकार अच्छी तरह से जानकारी कर ले, तो क्या फिर वह इसकी कीमत को घटायेगी ?

(Interruptions)

श्री दिनेश सिंह: सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय सदस्य श्री राजनारायण को मंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा ताकि वह अनुभव कर सके कि मंत्री किस तरह से काम करते हैं।

श्री राजनारायण: हां, हां, नहीं मिलेगा।

(Interruptions)

श्री दिनेश सिंह: अब सवाल यह है कि कपड़ा निर्धारित मूल्य से कम दाम पर बिक रहा है, उसके लिए क्या किया जाय अगर कपड़ा कम दाम पर बिक रहा है तो इसमें

क्या नुकसान है, यह तो बड़ी खुशी की बात है। कपड़े पर सीलिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि वह ज्यादा दाम पर न बिके। जब कपड़े निर्धारित दाम से भी कम दाम पर बिक रहा है तो अगर जरूरी हुआ तो अगली मर्तबा दाम निर्धारित करते वक्त इस पर गौर किया जायेगा।

SHRI M. S. OBEROI: May I ask the Minister if the Government has received any complaint from the consumers about overcharging in the prices and, if so, has the Government made any investigation and if an investigation has been made, what steps have been taken by the Government to stop it?

SHRI DINESH SINGH: Sometimes we get an odd complaint saying that they have not been able to get a particular variety at a particulr price and this is referred to the State Government for examination but I would not say that there is any general complaint as such that cloth is not available at controlled prices.

MINISTERIAL BODY IN ECAFE

*210. SHRI A. D. MANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Indian delegation to the ECAFE Conference at Tokyo advocated the setting up of a permanent ministerial body within ECAFE for a more efficient tackling of the problems of the region; and

(b) if so, what are the details of the proposals made by the Indian delegation?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SHRI A. D. MANI: The press has reported that such a speech was made by the Indian Delegation in the ECAFE Conference.

SHRI DINESH SINGH: What can I do about the press report? It is unfortunate.

SHRI A. D. MANI: May I ask whether any suggestion was made to this effect by any other Delegation?

SHRI DINESH SINGH: There was a suggestion for a Ministerial Conference which we made and it has been agreed to. There will be, we hope, a Ministerial Conference before the conference of the UNCTAD scheduled for next year.

(No hon. Member got up to put questions)

MR. CHAIRMAN: I am glad that for the first time nobody stands up.

*211. [*The questioner (Shri S. K. Vaishampayen) was absent. For answer,* vide *cols.* 1667—70 infra]

DELHI RING RAILWAY

*212. SHRI M. P. BHARGAVA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the work on Delhi Ring Railway is progressing according to schedule;

(b) if not, what are the reasons for delay; and

(c) whether any new target date has been fixed for completion of the project?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI S. C. JAMIR): (a) to (c) The sanctioned project is called "Delhi Avoiding Lines & Connected Traffic Facilities". The work has suffered a slight set back due to difficulties that had to be overcome in acquiring the land and also because the contract of one of the contractors had to be terminated on account of his failure in maintaining adequate progress, leading to a certain amount of delay. Possession of almost the entire land has recently been obtained and fresh tenders for completing the remaining part of the work have since been accepted and the work in all zones is now in full swing. The project is now expected to be completed in December, 1968, instead of December, 1967.